केस स्टडी

एक लम्बी सामुहिक लड़ाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना पूरा कराया

सलिहाभाटा /छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग दो सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोरबा जिले का एक महत्वपूर्ण पेशा क्षेत्र विकासखण्ड पोडीउपरोडा विकासखण्ड का एक महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत जो मुख्य सडक मार्ग से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । ग्राम सलिहाभाटा के आश्रित ग्राम पहाडों के उपर होने से इस ग्राम पंचायत को और दूर्गम बना देता है ।

इस ग्राम प्रचायत की आबादी महज 610 है जहां मनोहरा 98में बाला 101 व अतरौटी 42 आश्रितों की संख्या है । वहीं सलिहाभाटा में दलित 77 व अन्य पिछडा वर्ग 43 है।

सामाजिक एवं राजनैनिक स्थिति के कारण ग्रामीण जन मानस अपने आपको लाचार महशूस करता था । ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की भागीदारी नही के बतौर थी ।

महिलाए ग्राम सभा में बहुत काम भाग लेती थी ,जिसके कारण उन्हें ग्राम पंचायत व शासकीय योजनाओं की जानकारी का अभाव रहता था। परियोजना के प्रारम्भ के बाद यहां के हालात में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ ।ग्रामीण संगठन के निर्माण व योजनाओं तथा कानून की जानकारी होने से लोगों में लोग अपने अधिकार को लेने के लिए आगे आने लगे।

यहां के लोगों को एक धटना ने अपने संगठन के ताकत का एहसास करा दिया ।

धटना वर्ष 2013 –14 ग्राम पंचायत चुनाव के कुछ समय पूर्व की जब ग्राम पंचायत द्वारा करीब 10 लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया गया था ,लेकिन उन लोगों की स्वीकृत राशि उन तक नहीं पहुचने के कारण उनका मकान पूर्ण नहीं हो पा रहा था जिसके कारण ये

परिवार काफी परेशान थे उन्हें कोई रास्ता सूझ रहा था । ये परिवार अपने तरीके व अपनी पंहूच के अनुसार पिछले 6 माह से विभिन्न विभाग के अधिकारियो से सम्पर्क एवं चक्कर लगा रहे थे

प्रभावित परिवार के लोग अपनी आपबीति ग्रामीण बैठक के दौरान संगठन के लोगों की बताया ।तब संगठन के लोगों ने सभी प्रभावित परिवार के लोगों की बैठक लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं राजस्व कमिश्नर से सम्पर्क किये । तत्कालिन अनुविभागीय अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले ने स्वयं व्यक्गित रूची लेते हुए सभी प्रभावित परिवार का रूके हुए पैसा दिलाते हुए उनका मकान पूर्ण हो पाया ,जिससे लोगों को संगठन के ताकत का ऐहसास हो पाया ।